







# अर्थव्यवस्था की तस्वीर कोटोना के बाद साफ होगी

आज दश आर्थिक मदा के भयानक दलदल में फँस चुका है। कोरोना वायरस के चलते कई संप्रति देशों की जी डी पी नेटिव में जा पहुंची है। लेकिन भारत की हालत बहुत खराब है। करीब 24 प्रतिशत नेटिव अर्थव्यवस्था को देश कैसे संभाल पायेगा। अभी तीन साल पहले तक केंद्र सरकार और उसके चेला अर्थशास्त्री शेखी बघारे रहते थे कि जीडीपी को दर्हाई के आंकड़े में लाया जाएगा। कोरोनावायरस के प्रबंधन ने भी हमारी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था पर ग्रहण तो नोटबंदी और जीएसटी के समय से ही लगना शुरू हो गया था। पहले से ही मौजूद बेरोजगारों की फैज में कोरोना के कारण करोड़ों लोग और जुड़ गए हैं। हालांकि कहीं कोई रिकाउं नहीं है लेकिन डकैती, छिनौती, अपहरण, कल्प आदि की खबरों पर नजर ढालें तो लग जाएगा कि बेरोजगारों की बढ़ती फैज इस सब के लिए किसी हद तक जिम्मेदार मानी जानी चाहिए। 1991 में जब पीवी नरसिंहा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्हें एक ऐसी अर्थव्यवस्था की विरासत मिली थी जो कि तबाह हो चुकी थी। देश की आर्थिक विश्वसन्यता खत्म था। दश का रिजर्व सोना जहाज में लादकर विदेश ले जाया गया था और गिरवी रखा जा चुका था। पीवी नरसिंहाराव के वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पूंजीवादी अर्थिक चिंतन के खेमे के बड़े नाम थे। उन्होंने देश को अर्थिक विकास की ऐसी डगर पर डाल दिया जहां से हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई भी कहीं से भी हमला बोल सकता था। जब पीवी नरसिंहा राव की सरकार ने मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था की बात शुरू की थी तो सही अर्थिक सोच वाले लोगों ने चेतावनी दी थी कि ऐसा करने से देश दुनिया भर के पैसे वालों के रहमोकरम पर निर्भर हो जाएगा और मध्य वर्ग को हर तरफ से पिसाना पड़ेगा। सच्ची बात यह है कि जब बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास की योजना बना कर देश का अर्थिक विकास किया जा रहा हो तो कीमतों के बढ़ने पर सरकारी दखल की बात असंभव होती है। एक तरह से पूंजीपति वर्ग की कृषा पर देश की जनता को छोड़ दिया गया है। अब उनकी जो भी इच्छा होगी उसे करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। इसे देश का दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि शहरी

मध्यवर्ग के लिए हर चाज महगा है लेकिन इसे पैदा करने वाले किसानों को उसकी बाजिक कीमत नहीं मिल रही है। आज 24 फीसदी नेपेटिव जीडीपी की अर्थव्यवस्था में खेती ही वह क्षेत्र हैं जहाँ जीडीपी की पाजिटिव प्रोफ दुई है। लेकिन सरकार खेती वालों के बारे में कुछ भी करने को तैयार नहीं है। किसानों के कल्याण के लिए हरित क्रान्ति जैसी किसी क्रांतिकारी राजनीतिक और नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है। सप्लाई चेन को भी सही किया जाना सरकारी एजेंडा होना चाहिए। आज हालत यह है कि किसान से जो कुछ भी सरकार खरीद रही है उसका लागत मूल्य भी नहीं दे रही है। किसान को उसकी लागत नहीं मिल रही है और शहर का उपभोक्ता कई गुना ज्यादा कीमत दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बिचौलिया मजे ले रहा है। किसान और शहरी मध्यवर्ग की मेहनत का एक बड़ा हिस्सा वह हड्डप रहा है। और यह बिचौलिया ग़ा़मंडी में बैठा कोई आढ़ती नहीं है। वह बड़ा पूंजीपति भी हो सकता है और किसी भी बड़े नेता का व्यापारिक पार्टनर के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर आजादी के तुरत बाद का स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। व्यायोकि इसकी बुनियाद हमारे राजनेताओं ने उसी वक्त डाल दी थी जब उन्होंने आजादी के बाद महात्मा गांधी की सलाह को नजर रखा जरूर दिया था। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य में लिखा है कि स्वतंत्र भारत में विकास की यूनिट गांवों को रखा जाएगा। उसके लिए सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा परंपरागत ढांचा उपलब्ध था। आज की तरह ही गांवों में उन दिनों भी गरीबी थी। गांधी जी ने कहा कि आर्थिक विकास की ऐसी तरकीबें ईजाद की जाएं जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आर्थिक दशा सुधारी जा सके और उनकी गरीबी को खत्म करके उन्हें संपन्न बनाया जा सके। अगर ऐसा हो गया तो गांव आत्मनिर्भर भी हो जायेगे और राष्ट्र की संपत्ति और उसके विकास में बड़े पैमाने पर योगदान भी करेंगे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के लाखों गांव स्वतंत्र, शक्तिशाली और स्वावलंबी बनकर राष्ट्र के सम्पूर्ण जीवन में पूरा भाग नहीं लेते, तब तक भारत का भावी उज्ज्वल हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महात्मा गांधी

का साच का राजकाज का शला बनाने की सबसे ज्यादा योग्यता सरदार पटेल में थी। देश की बढ़किस्मती ही कही जायेगी कि आजादी के कुछ महीने बाद ही महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई और करीब ढाई साल बाद सरदार पटेल चले गए। उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे नेता थे जो महात्मा गांधी की हर बात मानते थे लेकिन अर्थिक नीति के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वे चूक गए। उहोंने देश के अर्थिक विकास की नीति ऐसी बनाई जिसमें गांवों को भी शहर बना देने का सपना था। उहोंने ब्लाक को विकास की यूनिट बना दी और महात्मा गांधी के बुनियादी सिद्धांत को ही छोड़ दिया। यहीं से गलती का सिलसिला शुरू हो गया। ब्लाक को विकास की यूनिट मानने का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि गांव का विकास गांव बालों की सोच और मर्जी की सीमा से बाहर चला गया और सरकारी अफसर ग्रामीणों का भाग्यविधाता बन गया। पर शुरू हुआ रिश्त का खेल और आज ग्रामीण विकास के नाम पर खर्च होने वाली सरकारी रकम ही गज्जों के अफसरों की रिश्त का सबसे बड़ा साधन है जब 1991 म यावा नरासह रख का सरकार आई तो अर्थिक और औद्योगिक विकास पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थशास्त्र की समझ पर आधारित हो गया। बाद की सरकारें उसी सोच को अगे बढ़ाती रहीं और आज तो हालात यह हैं कि अगर दुनिया के संपन्न देशों में बैंक फेल होते हैं तो अपने देश में भी लोग तबाह होते हैं। तथाकथित खुली अर्थव्यवस्था और वैशीकरण के चक्र में हमने अपने मुल्क को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जब हमारी राजनीतिक स्थिता भी दुनिया के ताकतवर पूंजीवादी देशों की मर्जी पर हो गई है। देश में अर्थिक मुसीबत की एक दूसरी समस्या है कि पिछले 40 वर्षों में राजनीति ऐसे लोगों का ठिकाना हो चुकी है जो आमतौर पर राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। आजादी की लड़ाई में बड़े पैमाने पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल लोग राजनीति में शामिल हुए थे। 1920 से 1942 तक भारतीय राजनीति में जो लोग शामिल हुए वे अपने क्षेत्र के बहुत ही सफल लोग थे। राजनीति में वे कुछ लाभ लेने के लिए नहीं आये थे, अपना सब कुछ कुबान करके अपन देश की अर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को लोकशाही के हवाले करने का उनका जज्जा उनको राजनीति में लाया था। बाद के समय में भी राजनीति में वे लोग सक्रिय थे जो आजादी की लड़ाई में शामिल रह चुके थे और देश के हित में कुर्बानियां देकर आये थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद जब से राजनीतिक नेताओं का नैतिक अधिकार कमजोर पड़ा तो राजनीति में ऐसे लोग आने लगे जिनके चापलूस कहा जा सकता है वे राजनीतिक जमातें भी राजनीति में सम्मान की उम्मीद करने लगीं जिनके राजनीतिक पूर्वज या तो अंग्रेजों के साथ थे या आजादी की लड़ाई में तमाशबीन की तरह शामिल हुए थे। उनको मान्यता मिली भी क्योंकि 1947 के पहले राजनीतिक संघर्ष का जीवन जीने वाले नेता धीरे-धीरे समाप्त हो रहे थे। आज दिल्ली में अगर नजर दौड़ाई जाए तो साफ नजर आ जाएगा कि राजनीति में ऐसे लोगों का बोलबाला है जो राजनीति को एक पेशे के रूप में अपनाकर सत्ता के गलियारों में धमाचौकड़ी मचा रहे हैं, देश के उज्ज्वल भविष्य से उनका कोई भला नहीं होने वाला है।

# बढ़ता रक्षा नियंत्रित

के 20 रक्षा उत्पाद नियांत्रक देशों की सूची में शामिल हो गया है। पिछलाहाल इसमें हमारा देश 19वें पायदान पर है। यह उपलब्धि इस अर्थ में और भी महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए रक्षा उत्पादन और नियांत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले महीने एक विशेष नीति बनाया है। इसमें इस क्षेत्र का विस्तार कर 2025 तक टर्नओवर 1.75 लाख करोड़ रुपये तथा नियांत्र 35 हजार करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की प्रतिबद्धता के परिणाम दिखने लगे हैं। घरेलू रक्षा उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में आयात एक अहम चुनौती है। लेकिन सरकार ने इसे प्रोत्साहन देने के लिए 101 सैन्य साजो-सामान के आयात पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदी लगाने का फैसला किया है। निवेश को सुगम बनाने के लिए अब सरकार ने रक्षा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का बड़ा निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में कोरोना संकट का सामना करने के विभिन्न उपर्योग व सुधारों का प्रस्ताव करते हुए ही कर दी थी। अब इस पर कैबिनेट की मुहर लग गयी है। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस निर्णय के साथ यह नियमन भी कर दिया गया है कि सरकार को ऐसे निवेशों की समीक्षा का अधिकार होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आने से निजी क्षेत्र के विस्तार का लाभ रक्षा उद्योग में लिया जा सकेगा। इसी क्रम में इस क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को बेहतर करने की जरूरत है ताकि उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के साथ उन्हें बदलते आर्थिक और तकनीकी रुझानों के अनुरूप बनाया जा सके। सैन्य प्रमुख (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने ऐसी कंपनियों में सुधार की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा है कि कार्य संस्कृति और गुणवत्ता को स्तरीय बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने कुछ पुराने उपकरणों और तकनीकों को उन देशों को नियंत्र करने का सुझाव भी दिया है, जिनकी रक्षा शक्ति कमज़ोर है। इससे हमारे यहां नयी तकनीक के लिए जगह भी बनेगी और नियांत्र से रणनीतिक व सामरिक संबंधों को भी मजबूत किया जा सकेगा। उनकी यह बात भी बेहद अहम है कि ताकतवर देशों की पाबंदियों की चिंता से भी भारत को निकलना चाहिए और अपने हितों के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए।

## किशोर बुद्धि का तजुर्जाल

एकशर उप्र क बच्चा क व्यवहार अवसर उनक नजदीका लागा का समझ में नहीं आता। ये लोग कुछ काम को एक खास तरीके से कर्ते हैं? हमारे बच्चे होते हुए भी हमसे व्याप्ति दुराव, छिपाव करते हैं? शैशव में सब कितना मधुर था- ऐसा हम लोग सोचते हैं। यहां यह जोड़ना जरूरी है कि ये परिवर्तन

सभी किशोरों और सभी अभिभावकों के ऊपर समान रूप से लागू नहीं है। किन्तु यह सच्चि का यह काल कठिन अवश्य है। लगभग सभी किशोरों के मुंह से प्रायरुद्ध यह सुनेंगे, कि आप हमसे यह चीज मत छीनिए, हमारे कर्म में मत आइए, हमारी चीजें मत छेड़िए। हमें खेलने दिजिए। टीवी देखना है, तो वे देखते चले जाएं। माता-पिता की अवहेलना करना, उनकी आदत बन जाती है। विशेष लक्षण- इस आयु में लोग अपने माता-पिता के प्रति हीन-भावना से ग्रस्त होते हैं, जबकि दूसरों के माता-पिता उन्हें सही लगते हैं। इस उम्र के लोग अपने दोस्तों, साथियों व कक्षा के सहपाठियों के साथ बहुत घुले-मिले, और अपने माता-पिता से अपने को अलग महसूस करते हैं। उन्हें कोई भी खिताब, इनाम जीतने की या नाम कमाने की असीम इच्छा होती है। उनकी इन्हीं प्रवृत्तियों को समझ कर उनके चरित्र को अचित दिशा में ढालने का यही समय होता है, जो उनके अभिभावक, शिक्षक या हितैषी में होना जरूरी है। समझने की बात यह है, कि किशोरों की ये प्रवृत्तियां मूर्खतापूर्ण, या जल्दबाजी की हों, किन्तु उनका मूल कारण समझना जरूरी है। क्या है वह मूल कारण? अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान को एक परियोजना में 90 के दशक में 160 किशोरों को किशोर बुद्धि के विकास का अध्ययन किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि 12 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष तक की आयु तक हमारी बुद्धि में कई तनुजाल विकास संबंधी परिवर्तन होते हैं। इस काल में बुद्धि की आधारभूत बनावट तो 90 फीसदी वही रहती है, जितनी छठ वर्ष की अवधि तक बनती है- और केवल खोपड़ी का आकार और मजबूती बढ़ती है, परन्तु बुद्धि के तनुजाल में क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं। इस काल में बुद्धि का एक तरह से पुनर्गठन होता है- जिसे अमेरीजी में नेटवर्क और वायररिंग अप्रेडेशन कहेंगे। जैसे, एक से दूसरी बात का संबंध समझना। बुद्धि के उन लम्बे कोसों पर जो कि दूसरे न्यूरोन्स को संदेश भेजने के तनु होते हैं, एक वसायुक्त श्वेत झिल्ली चढ़ जाती है, इस झिल्ली को(बुद्धि का श्वेत पदार्थ) कहा जाता है, जो कि एक्सोन्स के कार्य की गति को खूब तेज कर देती है। जबकि न्यूरोन्स जो बुद्धि को संदेश देने -लेने वाला पदार्थ है, पर डेन्ड्राइट्स (शाखाएं) भारी संख्या में मजबूती से उड़ा आती है। पर दूसरे शब्दों में इसमें घनत्व और मजबूती बढ़ती है। उसके एक्सोन्स के गिर्द बने

# ਜੇਹਣਾ ਵ ਪਪਲਾਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪਟਾ

को अपर्खल दिया जायेगा। ब्रिटेन में एक वॉलटियर को वैक्सीन देने के बाद कुछ परेशानी हुई है। इसके बाद ट्रायल को बहाँ रोक दिया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जेनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआई) ने नोटिस जारी कर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से संवाल किया है कि दूसरे देशों में चल रहे ट्रायल के नतीजों के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका पोएलसी की ओर से इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। भारत में इस पर रोक लगायी गयी है, तो कोई नयी बात नहीं है। वैक्सीन ट्रायल में काफ़ी लोगों को शामिल किया जाता है। जब ट्रायल के दौरान किसी को वैक्सीन दी जाती है, तो उसमें कई लोगों को पहले से भी बीमारी होती है। पहले और दूसरे फेज की जब स्टडी की जाती है, तो हर एक व्यक्ति की पहले क्लीनिकल जांच की जाती है। उसे देखा जाता है कि उस व्यक्ति को कहीं पहले से काई और बीमारी तो नहीं है। लेकिन, जब तीसरे फेज का ट्रायल होता है, तो उसमें सामान्य जनता को चुना जाता है। उसमें पहले से लोगों की जांच नहीं की जाती है। आगे किसी को कोई बीमारी रही है, उसे दिक्कत हो जाये, तो कह दिया जाता है कि वैक्सीन की वजह से है। होता है और वैक्सीन बनाने वाले के साथ उनका कोई मतलब नहीं होता है। यह निकाय जांच करता है कि जो दिक्कत आयी है, क्या वह वैक्सीन के कारण है या किसी अन्य वजह से है। इसी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई निर्भर होती है। हालांकि, कमेटी की इस संदर्भ में बैठक नहीं हुई है। इसमें एक-दो दिन का समय लगता है। इसलिए, जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह क्या रही, उसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। यह ठीक उसी तरह से है किसी ने पानी पीया और उसे सांप काट लिया। लेकिन जिन्हें मालम नहीं कि सांप ने काटा है, वे कहेंगे कि पानी पीने की वजह से उसकी मौत हो गयी। पानी में कुछ मिला हुआ था। ये निराधार बातें हैं। इसलिए, जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उक कारण स्पष्ट हो पायेगा। खबरों में कहा गया है कि ट्रायल के दौरान एक वॉलटियर को ट्रायल्सर्स मायलाइटिस का पता चला। हालांकि, इसकी पुष्ट अभी नहीं हुई है। यह बीएसएमबी की मीटिंग के बाद ही हो पायेगी। इस वैक्सीन का पहला और दूसरा चरण काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वैक्सीन की वजह से कोई दिक्कत उत्पन्न हुई होगी। पहले और दूसरे

रिस्पांस है. देखा जाता है कि इम्यून का रिस्पांस क्या बाकई वायरस को मार देने में सक्षम है या नहीं. न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज के बनने के बारे में भी पता लगाया जाता है. यह दो तरह का एक सेलुलर रिस्पांस और दूसरा ह्यूमलर रिस्पांस होता है. सेलुलर रिस्पांस के अंदर टी सेल्स आदि को देखते हैं. यह लंबे समय की इम्युनिटी के लिए काम करती है. फेज एक और दो में सेफ्टी और इम्युनोजेनेसिटी देखा जाता है. जिन वैक्सीन को अप्फ्लवल दिया गया है, उसमें सेफ्टी और इम्युनोजेनेसिटी का कोई इश्यू नहीं था. लेकिन, फेज तीन में इसके असर को लंबे समय तक परखा जाता है. जो एंटीबॉडीज बनी वह कितनी देर तक प्रोटेक्शन देती है. सेफ्टी से जुड़े मामले फेज तीन में ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं. अभी सभी वैक्सीन डेकलपमेंट स्टेज में हैं. दुनिया में केवल तीन वैक्सीन को अप्फ्लवल मिला है. लेकिन, यह इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए है. इसमें रूस की स्पुतनिक वैक्सीन और दो चीनी वैक्सीन हैं. इन वैक्सीन की फेज तीन के सीमित ट्रायल के बाद अप्फ्लवल दिया गया. लेकिन, लंबी अवधि में सुरक्षित वैक्सीन का आना अभी बाकी है. सेफ्टी के लिए जरूरी है कि इसके प्रभावों को बारीकी से जांचा जाये. जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते, उसे सामान्य जनता को नहीं दिया जा सकता है. आजकल इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जाती है. बहुत सारी मेडिसिन के लिए भी इजाजत दी जाती है. भारत में सीरम के अलावा बाकी जो तीन-चार कंपनियों की वैक्सीन हैं, वे शुरूआती चरण में हैं. इसमें जायडस, भारत बायोटेक की वैक्सीन है, उन्हें फेज दो के ट्रायल का अप्फ्लवल मिला है. लेकिन, वैक्सीन का सबसे अहम चरण तीसरा ही होता है. कितनी देर तक इम्युनिटी और सेफ्टी रहती है, इसी चरण में देखा जाता है. कुछ रिएक्शन तुरंत होते हैं, कुछ में छह से आठ महीने का समय लगता है. इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन छह महीने या आठ महीने बाद उतनी कारगर है कि नहीं यह भी देखा जाता है. जहां तक अन्य ट्रायल की बात है, तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. क्योंकि हर एक की टेक्नोलॉजी और तरीके अलग-अलग होते हैं. अभी एक वैक्सीन के ट्रायल को कुछ समय के लिए रोका गया है, बाकी अन्य पर काम चलता रहेगा. वैक्सीन ट्रायल के दौरान दो बातों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाता है. पहला सेफ्टी और दूसरा इम्युनोजेनेसिटी. यानी वैक्सीन किसी को भी, किसी भी उम्र में लगे, तो उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. वैक्सीन जिस कारण के लिए लगा रहे हैं, उसमें वायरस के अटैक से बचाव कर सकता है या नहीं, यह भी देखना जरूरी होता है।

वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में भारी गिरावट आयी है। लेकिन संपूर्ण वर्ष की जीडीपी में 2020 के बाद पहली बार अगस्त 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। वर्ष के रूप में विकसित किया जाये। कोविड-19 के बीच चीन के प्रति दुनिया की बढ़ती नाराजगी के



हालांकि भारतीय प्रबन्धालयों ने लॉकडाउन के दौरान सभी सेवाएँ बंद की थीं। यहाँ तक कि जीडीपी की विशेषज्ञ समिति ने भी अपनी वार्षिक बैठक को रद्द कर दिया। लॉकडाउन के दौरान भारतीय सेवाएँ बंद रखी गई थीं। इसके बाद जीडीपी ने अपनी वार्षिक बैठक को रद्द कर दिया। यह बैठक को रद्द करने की वजह यह थी कि जीडीपी की विशेषज्ञ समिति के चेयरमैन केवल कामत ने कहा कि जीडीपी की वृद्धि दर में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में गिरावट के बाद आगामी तिमाहियों में जीडीपी की स्थिति में तेजी से बेहतर सुधार की उमीद है। कई देशों की तरह भारत में भी कोविड-19 के कारण जीडीपी में भारी गिरावट का परिवृश्य दिखायी दे रहा है। लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

जो राष्ट्रीय सांख्यिकीय विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में देश के जीडीपी में -23.9 फीसदी की बड़ी गिरावट आयी है। यह गिरावट कस्ट्रक्शन सेक्टर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल सेक्टर, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में, फ़िल्मेंशियल सर्विस सेक्टर और उपयोगी सेवाओं के सेक्टर दिखायी दी है। कृषि ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है, जिसमें 3.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गयी है। दुनिया के आर्थिक एवं निधन साल 2019 में इसी निहान में हुई बित्री को पीछे छोड़ दिया है। बढ़ती हुई रेलवे माल ढुलाई आर्थिक गतिविधियों की बेहतर संकेतक है। साथ ही बिजली की खपत में भी अच्छी सुधार हुआ है। आइएचएम मार्केट इंडिया के मैन्यूफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजस इंडेक्स (पीएमआई) अगस्त 2020 में 52 दर्ज हुआ है। पीएमआई इंडेक्स जुलाई में 46 दर्ज हुआ था, जबकि अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान यह 41 दर्ज हुआ था।



